नियरों के संघ ने सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की असफलताओं से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की असफलताओं के संबंध में संघ के ज्ञापन में किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है और उसमें दर्शायी गयी कमियों के कारण इस संस्थान को प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है, और क्या सरकार इन कमियों को तत्काल दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित ज्ञापन की विषय-वस्तु की उपयुक्त कार्यवाही हेतु जांच की जा रही है ।

दालों का उत्पादन

1840. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशकों के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दो दशक पूर्व सकल खाद्यान्न-उत्पादन में दालों के उत्पादन का जो प्रतिशत था, वह इस दशक के अंत में बरकरार नहीं रह पाया है;

(ग) यदि हां, तो सकल खाद्यान्न-उत्पादन में दालों के उत्पादन का प्रतिशत कितना है, और क्या यह सच है कि उसके परिणामस्वरूप दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में अत्याधिक कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो साठ के दशक के आरम्भ में और अस्सी के दशक के अन्त में दालों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता कितनी-कितनी थी; और

(ङ) दालों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुरूप दालों की प्रति-व्यक्ति–प्रति दिन उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है और इस अवधि के दौरान देश में दालों का कितना उत्पादन होगा तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार किसानों को क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में से दालों की प्रतिशतता 1970–71 के दौरान 10.9 प्रतिशत थी जो कि 1989–90 के दौरान घटकर 7.4 प्रतिशत हो गई । इस अवधि में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है ।

(घ) 1960 तथा 1990 में दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता क्रमशः 65.5 और 36.5 (अनन्तिम) ग्राम प्रतिदिन थी ।

(ङ) 1991–92 के दौरान, दालों के उत्पादन का लक्ष्य 155.0 लाख मीटरी टन नियत किया गया है । दालों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है । दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दो योजनाएं अर्थात् केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और केन्द्रीय क्षेत्र विशेष खाद्यान्न उत्पान कार्यक्रम–दलहन कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मूल्य समर्थन/मण्डी हस्तक्षेप उपाय भी किए जा रहे हैं ताकि देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के उच्चतर स्तर को प्राप्त किया जा सके ।